

Uttar Pradesh as the Center of National Politics: An Analytical Study

Luxmi and Shivangi Kashyap

Department of Political science, Raghunath Girls PG College, Meerut-250 001, U.P., India

Department of Political Science, BHU, Varanasi-221005, U.P., India

shivi21kashyap@gmail.com

Received: 27-08-2024, Accepted: 18-12-2024

Abstract- Uttar Pradesh plays a significant role in Indian national politics. This research paper analyzes the political importance of Uttar Pradesh while reviewing its historical, social, and cultural aspects. The study highlights the contributions of major political movements, parties, and leaders from Uttar Pradesh who have played a crucial role in shaping national politics. Additionally, it examines the prominent role of Uttar Pradesh in Lok Sabha elections and the political outcomes arising from it. This paper is an attempt to understand the evolving political landscape of Uttar Pradesh and its impact on national politics. The study makes it clear that Uttar Pradesh is an integral part of India's political framework, not only from a political perspective but also in terms of its social and cultural context.

Key words- National politics, Lok Sabha elections, political movement, social impact, cultural contribution, Indian democracy

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

लक्ष्मी¹ एवं शिवांगी कश्यप²

¹राजनीति शास्त्र विभाग, रघुनाथ गल्लर्स पी0जी0 कॉलेज, मेरठ-250 001, उ0प्र०, भारत

²राजनीति शास्त्र विभाग, बी0एच0य०, वाराणसी-221 005, उ0प्र०, भारत

shivi21kashyap@gmail.com

सार— उत्तर प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस शोध-पत्र में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महत्व का विश्लेषण करते हुए, इसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समीक्षा की गई है। अध्ययन में उत्तर प्रदेश के प्रमुख भूमिका निभाई रखी गई है। साथ ही, लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका और इससे उत्पन्न राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण किया गया है। यह शोध-पत्र उत्तर प्रदेश के बदलते राजनीतिक परिदृश्य और राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव को समझने का एक प्रयास है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी भारत के राजनीतिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है।

बीज शब्द— राष्ट्रीय राजनीति, लोकसभा चुनाव, राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक योगदान, भारतीय लोकतंत्र

1. परिचय— हिन्दुस्तान का दिल और दिमाग कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीतिक क्षेत्र में विशेषज्ञों की राय सदैव रही है कि केंद्र की सत्ता का सफर उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ होकर यहीं पर केंद्रित रहता है। अर्थात् केंद्र में वर्चस्व स्थापित करने के लिये प्रदेश में अपना राजनीतिक प्रभाव बनाना अति आवश्यक है। विगत 75 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इस देश की राजनीति को संवारकर उसे नई दिशा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश वह विशाल गुरुत्वाकर्षण है जिसके स्पर्श के बिना हमारे देश की राजनीति परिपूर्ण नहीं होती। इस राज्य ने भारत की राजनीति को विविध आयाम दिया है।

इस संदर्भ में सर्वप्रथम प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को समझने से पूर्व इसके अतीत को समझना आवश्यक हो जाता है। देश में अच्छा बुरा जो कुछ हुआ, उसकी जड़े आपको इसी प्रदेश में मिलेंगी। इसी राज्य ने देश को स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाकर देश को स्वाधीनता का स्वाद चखाया। लेकिन साथ ही इसकी विडंबना रही कि देश के बंटवारे की मांग भी यहीं से उठी। मंडल के बाद सामाजिक बिखराव के बीज भी इसी प्रदेश में पड़े। धर्म और राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला मथुरा, काशी, अयोध्या यहीं बनी। उत्तर प्रदेश से ही इस्लाम की दुनियाभर में प्रसिद्ध दो धाराओं ने जन्म लिया। बरेलवी और देवबन्दी फिर से इसी प्रदेश की धरा पर जन्मे और सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में इनका प्रसार हुआ। जैसा कि सर्वविदित है तालिबानियों की तालिमी जड़े देवबन्द में ही है। इन फिरकों का जिक इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि, ये उत्तर प्रदेश की जमीन के उपजाऊ तासीर के गवाह हैं, ये तासीर जितनी सियासी है उतनी मजहबी भी है। बरेलवी और देवबन्दी तबकों का जिक जितना धर्म के लिए हुआ, उतना सियासत के लिये भी। अयोध्या, काशी, मथुरा, बरेलवी देवबन्दी यह वह तत्व है जिससे देश के सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण का “न्यूकिलयस” यह उत्तर प्रदेश बना।¹⁻¹⁰

2. लोकसभा चुनावों का इतिहास—15 अगस्त, 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना और उसके प्रावधानों के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से चुनी सरकार को देश की सत्ता की बागड़ेर देने का फैसला हुआ। लोकसभा चुनाव भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का आधार है जो 1952 में पहले आम चुनाव के साथ प्रारम्भ हुए। समय के साथ, ये चुनाव राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साक्षी रहे हैं। प्रत्येक चुनाव ने देश की राजनीतिक स्थिति को दर्शाया है और मतदाताओं की प्राथमिकताओं में परिवर्तनों को उजागर किया है। सन् 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था जो लम्बे समय तक कायम रहा। बाद में, विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी भूमिका स्थापित की।

लोकसभा चुनाव न केवल राजनीतिक दलों की ताकत को मापने का पैमाना है बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का माध्यम भी है। प्रत्येक चुनाव के साथ, भारत ने लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। देश का पहला आम चुनाव 1952 में होता है, जिसके परिणाम के साथ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दिल्ली केंद्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए, उत्तर प्रदेश पर राजनीतिक पकड़ होना आवश्यक है। सर्वविदित है कि प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीट है। जो कि देश की राजनीति का पूरा समीकरण बदलने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, राजनीतिक दलों ने सदैव से इस तथ्य को गांठ बांध रखा है कि केन्द्र में जगह बनाने के लिए प्रदेश में वर्चस्व स्थापित करना अनिवार्य है।

देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले इस प्रदेश से 22 साल पहले 1999 के आम चुनाव तक 543 सदस्यों वाली लोकसभा में 85 जन प्रतिनिधि इस प्रदेश से भेजे जाते थे। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद, वर्तमान में 80 जन प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और अनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत 31 सदस्य राज्यसभा के लिये चुने जाते हैं। इस आंकड़ों से भी दिल्ली की राजनीति में उत्तर प्रदेश की महती भूमिका उजागर होती है।¹¹⁻¹⁸

3. लोकसभा चुनाव (1952–2024)

उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का मुख्य बंटवारा

चुनावी वर्ष	केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी/गठबंधन	उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा
1952	कांग्रेस	कांग्रेस -81, सोशलिस्ट पार्टी-02, अन्य-02
1957	कांग्रेस	कांग्रेस-70, अन्य-15
1962	कांग्रेस	कांग्रेस-62, अन्य- 23
1967	कांग्रेस	कांग्रेस-47, भारतीय जन संघ-12, अन्य-26
1971	कांग्रेस	कांग्रेस-73, भारतीय जन संघ-4, अन्य- 08
1977	जनता पार्टी	भारतीय लोक दल-85
1980	कांग्रेस	कांग्रेस -51, जनता पार्टी (सेक्युलर)-29, अन्य-5
1984	कांग्रेस	कांग्रेस -83, लोक दल- 02
1989	जनता दल +	बी0जे0पी0-08, कांग्रेस-15, जनता दल -54, बी0एस0पी0-2 , अन्य-6

शोध पत्र

1991	कांग्रेस	बी०जे०पी०-51, कांग्रेस -5, जनता दल-22, अन्य-7
1996	जनता दल +	बी०जे०पी०-52, एस०पी०-16, बी०एस०पी०-6, कांग्रेस-5, अन्य-06
1998	भाजपा +	बी०जे०पी०-57, एस०पी०-20, बी०एस०पी०-4, कांग्रेस एवं अन्य-04
1999	भाजपा +	बी०जे०पी०-29, एस०पी०-26, बी०एस०पी०-14, कांग्रेस -10, अन्य-06
2004	कांग्रेस +	बी०जे०पी०-10, कांग्रेस-9, बी०एस०पी०-19, एस०पी०-35, अन्य-7
2009	कांग्रेस +	यूपीए-21, एन०डी०ए० -15, थर्ड फ्रन्ट-20, फोर्थ फ्रन्ट-23, अन्य-1
2014	भाजपा +	बी०जे०पी०-71, एस०पी०-5, अपना दल-2, कांग्रेस-2
2019	भाजपा +	एन०डी०ए०-64, महागठबंधन-15, यूपी०ए०-01
2024	भाजपा +	इंडिया एलाइन्स-43, एन०डी०ए०-36, अन्य-01

4. विश्लेषण- जैसा कि पूर्व में यह स्पष्ट किया गया है कि विगत 75 वर्षों में, अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से कुल नौ हुए हैं, जिनमें जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गाँधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गाँधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी बाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी इसी प्रदेश से हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में केवल उत्तर प्रदेश में ही देश को अभी तक अधिकतर प्रधानमंत्री दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों से छह प्रधानमंत्री हुए। उनमें वी.पी. सिंह को छोड़ दिया जाए, तो अन्य पांच प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश की वजह से ही दिल्ली में सत्ता प्राप्त करने में सफल हो पाए थे।

भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लगातार सत्ता में बने रहने के पीछे भी, उत्तर प्रदेश का ही अहम योगदान है। नरेंद्र मोदी भले ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन लोकसभा तक पहुंचने का रास्ता और राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को स्थापित करने के लिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के दामन का ही सहारा लिया। उन्होंने गुजरात की जगह संसद में उत्तर प्रदेश की 80 में से एक लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। शायद इसलिए कि उन्हें इस बात का आभास पहले से था कि गुजरात की अपेक्षा उत्तर प्रदेश से जुड़ने पर, देश की राष्ट्रीय राजनीति में अधिक मान्यता और लोकप्रियता मिलेगी।

देश के पहले आम चुनाव जो कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला, में यह तस्वीर साफ हो चुकी थी कि पिछले करीब 75 सालों में, राष्ट्रीय राजनीति के सफर में राजनीतिक दलों के पास दिल्ली की केंद्रीय सत्ता तभी तक रही जब तक उत्तर प्रदेश में उनकी जड़े फैली रही। प्रदेश में अगर वह कमजोर हुई तो राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका स्तर समय के साथ-साथ गिरता संभलता रहा, भले ही वह दूसरे राज्यों और दक्षिण के राज्यों में अपनी पकड़ बनाए रखने में क्यों ना सफल रहे हो। यह सच कांग्रेस या भाजपा की सरकार पर ही लागू नहीं होता, अपितु केंद्र में गठबंधन की जो भी सरकार बनी, उनमें भी उस पार्टी का बोलबाला ज्यादा रहा, प्रभाव ज्यादा रहा जिसने उत्तर प्रदेश में बखूबी चुनावी प्रदर्शन किया था।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, सन् 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल रही। इस दौरान केंद्र में भी वो सत्ता में बनी रहे, लेकिन इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश की 85 में वह एक भी सीट नहीं जीत पाई, क्यों? इसके पीछे भी एक विशेष कारण था और वह कारण यह था कि आपातकाल के तुरंत बाद हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वह विधानसभा की 518 सीटों में केवल 47 सीटों पर ही जीत प्राप्त कर पाई थी। उस समय जनता पार्टी की सभी 85 लोकसभा सीटों पर जीत हुई थी, और विधानसभा चुनाव में भी उसे 352 सीटें मिली थी। जो कि सीधा उसको केंद्र की सत्ता की तरफ ले जा रही थी और हुआ भी यहीं, कि केंद्र और प्रदेश दोनों में जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन 3 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस ताकतवर होकर उभरी। लोकसभा में उसे 50 सीटें मिलीं। उसी साल विधानसभा के हुए चुनाव में वह 309 सीटें पर जीती। प्रदेश और केंद्र दोनों जगह वापस कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में भी पिछले चुनाव की तरह ही परिणाम रहा। उत्तर प्रदेश की 85 में से 83 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। कुछ महीने बाद 1985 में प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस 269 सीटें जीतकर केंद्र के साथ प्रदेश में भी सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन इस चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ धीरे-धीरे कमजोर होती गई क्योंकि उसका जनाधार सिमटता गया। जिसका सीधा प्रभाव देश की राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिला।

इस परिवर्तन के विशेष कारण थे, हम इनका विश्लेषण भी करेंगे। वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस को यू.पी. में पिछले वर्ष की चुनाव की तुलना में 68 सीटें कम मिली थी। उसे प्रदेश की 85 लोकसभा सीटों में केवल 15 लोकसभा सीटों में केवल 15 लोकसभा सीटों पर संतोष करना पड़ा था। यदि वास्तविक धरातल पर यह विश्लेषण किया जाए, तो 1989 से 1990 की सीमा रेखा को राजनीति के लिहाज से मील का पथर माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और देश की राजनीति पर उसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। उससे पहले इस परिवर्तन का एक असर यह भी हुआ कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार अपनी सरकार बना रही थी। लेकिन उसके बाद, वह उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाई। इसी तरह इन 30 वर्षों में नरसिंहराव की अल्पमत की सरकार को छोड़ दें, तो केंद्र में भी कांग्रेस कभी भी अपने बल पर सरकार नहीं बना पायी है। जिसका स्पष्टीकरण यह है कि प्रदेश में उसकी जड़े दिन—प्रतिदिन कमजोर होती चली गई जिसके उबरने के लिए कहीं न कहीं कांग्रेस आज भी प्रयास कर रही है।¹⁹⁻²⁰

दूसरी तरफ प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा था और इसकी सहभागिता एवं मांग देश की केंद्रीय राजनीति में भी बढ़ने लगी थी। अगर हम उत्तर प्रदेश के केंद्रीय राजनीति में प्रभाव एवं महत्व को समझना चाहते हैं तो इसे तीन चरणों में विभाजित करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें 1990 से लेकर 2019 तक के राजनीतिक यात्रा में उत्तर प्रदेश की भूमिका के महत्व को देखा जा सकता है।

पहले चरण में उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ जातीय आधार पर बनी क्षेत्रीय दलों के बीच प्रदेश की सत्ता की दावेदारी को लेकर संघर्ष चलता रहा। कभी इनकी गुटबाजी होती तो कभी—कभी अपने साख को बनाए रखने को लेकर मतभेद। लेकिन मुद्दे की बात तो यह थी कि इन सब में भाजपा ने प्रदेश में अपने राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार बखूबी किया। जिसका सीधा प्रभाव केंद्र में भी देखने को मिला।

इस सफर के दूसरे चरण भी बहुत महत्व पूर्ण रहे, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व सपा एवं बसपा से ज्यादा ताकतवर होकर उभरा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के साथ जातीय आधार पर बनी क्षेत्रीय दलों के बीच प्रदेश की सत्ता की दावेदारी को लेकर संघर्ष चलता रहा। कभी इनकी गुटबाजी होती तो कभी—कभी अपने साख को बनाए रखने को लेकर मतभेद। लेकिन मुद्दे की बात तो यह थी कि इन सब में भाजपा ने प्रदेश में अपने राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार बखूबी किया। जिसका सीधा प्रभाव केंद्र में भी देखने को मिला।

तीसरे चरण में हम 2014 से 2019 तक के राजनीतिक परिदृश्य को समझ सकते हैं। जिसको प्रदेश में भाजपा के पुनर्जन्म के रूप में देखा जाता है। क्योंकि यही वह समय था जब उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी पकड़ फिर से मजबूत बनानी शुरू कर दी थी। जिसका आधार उसने प्रदेश में नए सामाजिक समीकरण और हिंदुत्व की नई लहर जैसे मुद्दों का आधार बनाकर किया, जिसका सीधा लाभ बी.जे.पी. को 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। इस दौरान बी.जे.पी. ने कई लगातार पारियाँ खेलीं और जीती भी जिसका एकमात्र मंच उत्तर प्रदेश ही था।²¹⁻²⁶

5. निष्कर्ष—इस शोध पत्र में यह स्पष्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ऐतिहासिक रूप से, राज्य ने न केवल प्रमुख राजनीतिक आंदोलनों और दलों को जन्म दिया है, बल्कि प्रभावशली नेताओं की एक लंबी श्रृंखला का योगदान भी दिया है, जिन्होंने भारत की राजनीति को दिशा प्रदान की है। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की निर्णायक भूमिका, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक निभाने के साथ मिलकर, इसे राष्ट्रीय राजनीति के लिये अपरिहार्य बनाती है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य समय के साथ बदलता रहा है, जिसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय राजनीति और समाजवादी आंदोलनों का बड़ा योगदान रहा है।

उपरोक्त समस्त घटनाक्रमों को देखे तो, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि केंद्र की राजनीति और दिल्ली की सत्ता के लिए किसी राजनीतिक दल या उनके गठबंधन के लिये उत्तर प्रदेश में उपरिथिति का अत्यधिक महत्व है, जिसके लगभग सभी राजनीतिक दल भलीभांति समझते हैं। यही कारण है कि दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पूरे भारतवर्ष की निगाहें टिकी रहती हैं। हालांकि प्रदेश के चुने हुए विधायक केंद्र की सरकार नहीं तय करते, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि प्रदेश चुनाव के परिणाम लोकसभा के चुनाव की दशा और दिशा निर्धारित कर दिल्ली के बैठने वाली सरकार का भविष्य जरूर तय करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश आंरभ से ही देश के संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य में एक “पॉवर हाउस” की तरह भूमिका निभाता रहा है। इस राज्य ने सदैव से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती दी है और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया है।

शोध पत्र

अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश न केवल एक राज्य है, अपितु भारतीय राजनीति की धुरी है, जो देश की राजनीति और नीतियों को गहराई से प्रभावित करता है। भविष्य में भी, उत्तर प्रदेश की यह भूमिका और अधिक सशक्त होने की संभावना है। इस प्रकार समस्त तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समय के साथ देश में राजनीति का मौसम भले ही बदलता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भूमिका को देखते हुए इसके महत्व को राष्ट्रीय राजनीति के यात्रा में स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है।

References

1. Election Commission of India. "Lok Sabha Election Results (1952-2017)." Official Website of Election Commission of India.
2. Tripathi, Ramesh. "Contribution of Uttar Pradesh in Indian Politics." New Delhi: Rashtriya Prakashan, 2015.
3. Yadav, Suresh. "Uttar Pradesh and National Politics: A Historical Perspective." Lucknow: Uttar Pradesh Publication Department, 2018.
4. Verma, Ajay Kumar. "Impact of Caste and Regionalism in Indian Politics." Varanasi: Kashi Vidyapeeth Press, 2016.
5. Goswami, Preetam. "Political Status of Uttar Pradesh and its Impact on National Politics." Indian Political Research Journal, Vol. 12, Issue 4, 2019.
6. Kumar, Shashi. "Socialist Movement and Uttar Pradesh." Lucknow: Sahitya Bhavan, 2014.
7. Mishra, Arvind. "Democracy and Electoral Politics." New Delhi: India Publication, 2020.
8. Chauhan, Manish. "Role of Uttar Pradesh in Indian Politics." Social Science Journal, Vol. 8, Issue 3, 2017.
9. Indian Parliamentary Institute. "Development of Lok Sabha and Rajya Sabha in India." New Delhi: Parliamentary Publication, 2015.
10. Joshi, Vipin. "Historical Development of National Politics and Uttar Pradesh." Varanasi: Gyandep Prakashan, 2013.
11. Dubey, Shailendra Kumar. "Democracy and Caste Politics: A Study of Uttar Pradesh." Varanasi: Kashi Vidyapeeth Prakashan, 2018.
12. Goswami, Preetam. "Regional Politics of Uttar Pradesh and its National Impact." Delhi: Oxford University Press, 2015.
13. Yadav, Ramgopal. "Socialist Movement in Indian Politics." Agra: Sahitya Bhavan, 2014.
14. Mishra, Arvind. "Political Sociology: A Special Reference to Uttar Pradesh." Kolkata: Asian Books, 2017.
15. Chauhan, Rakesh. "Role of Uttar Pradesh in Indian National Movement." Meerut: Surya Prakashan, 2016.
16. Singh, Shivshankar. "Development of Caste-based Politics in India." Patna: Mithila Publication, 2015.
17. Shukla, Umesh. "Indian Political System and Uttar Pradesh." Lucknow: Ganga Publication, 2018.
18. Jain, Anil. "Uttar Pradesh: Electoral Politics and National Impact." Jaipur: Sahitya Sadhna Prakashan, 2020.
19. Indian Parliamentary Institute. "Historical Development of Lok Sabha and Rajya Sabha." New Delhi: Parliamentary Publication, 2016.
20. Sharma, Mohanlal. "Uttar Pradesh and Political Polarization." New Delhi: Penguin India, 2019.
21. Gupta, Nirmal. "Cultural Diversity and Political Impact of Uttar Pradesh." Lucknow: Navbharat Prakashan, 2021.
22. Verma, Manoj. "Analysis of Uttar Pradesh in National Politics." Patna: Prakashan Bharati, 2019.
23. Chaudhary, Ajay. "Democracy and Politics: Changing Dimensions of Uttar Pradesh." Delhi: Alok Publishers, 2020.
24. Thakur, Subhash. "Uttar Pradesh and Indian Federal Politics." Chandigarh: Haryana Book Depot, 2018.
25. Indian Political Research Center. "Electoral Strategies and Policy Impacts of Uttar Pradesh." Delhi: Research Publication, 2021.
26. Tiwari, Hemant. "Contribution of Political Parties in Uttar Pradesh to Indian Politics." Kanpur: Kanpur University Press, 2020.